रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 27, 1988/फाल्गुन 8, 1909
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 27, 1988/PHALGUNA 8, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Ministries of the Government of India (other than Statutory Orders and Notifications issued by the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा विभाग)

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1988

का. आ. 392.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 33 के अधीन इसके द्वारा प्रयोज्य शक्तियां, श्री कुलदीप राय, उप सचिव, गृह मंत्रालय (पुनर्वास प्रभाग) द्वारा प्रयोज्य होंगी।

2. इसके द्वारा इस विभाग की दिनांक 17 जुलाई, 1986 की अधिसूचना संख्या 1 (10)/वि. सेल/86-एस. एस. II (ए) का अतिक्रमण किया जाता है।

[संख्या 1(8)/वि.सेल/87-एस एस II(ए)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Internal Security)

(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 7th January, 1988

S.O. 392.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government, hereby direct that the powers exercisable by it under Section 33 of the said Act shall be exercisable by Shri Kuldip Rai, Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs (Rehabilitation Divison).

2. This supersedes this Department's Rehabilitation Division's Notification No. 1(10)/Spl. Cell/86-SS.II(A) dated 17th July, 1986.

[No 1(8)/Spl. Cell/87-SS II(A)]

का. आ. 393.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन इसके द्वारा प्रयोज्य शक्तियां, श्री कलदीप राय, उप सचिव, गृह मंत्रालय (पुनर्वास प्रभाग) द्वारा प्रयोज्य होंगी।

2. इसके द्वारा इस विभाग की दिनांक 17 जुलाई, 1986 की अधिसूचना संख्या -1 (10)/वि. सेल/86-एस. एम. II (सी) का भी अतिक्रमण किया जाता है।

[संख्या -1 (8)/वि. सेल/87-एम. एस. II (बी)]

S.O. 393.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby direct that the powers exercisable by it under Sub-section (4) of Section 24 of the said Act shall be exercisable by Shri Kuldip Rai, Deputy Secretary in the Ministry of Home Affairs, Department of Intersal Security Rehabilitation Division.

2 This also supersedes this Department's Rehabilitation Division's Notification No| 1(10)|Spl. Cell|86-SS.II(C) dated 17-7-86.

[No. 1(8)|Spl. Cell|87-SS.II(B)]

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1988

का. आ. 394 :—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भूतपूर्व पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) में भारत सरकार की दिनांक 30-8-1974 की अधिसूचना संख्या -2 (8) /वि. सैल/69-एम. एस.-4 में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 33 के अधीन राज्य के अंतर्गत तथा "प्रतिकर पूल" का भाग भूमि और संपत्तियों के संबंध मे इसके द्वारा प्रयोज्य शक्तियां, विशेष कार्य अधिकारी (अपील एवं पुनरीक्षण) महाराष्ट्र सरकार, राजस्व और वन विभाग द्वारा भी उनके अपने कार्य के अतिरिक्त प्रयोज्य होंगी।

[संख्या 1 (5)/वि. सैल/ 86-एम. एम. II]

जी. पी. एस. साही, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 14th January, 1988

S.O. 394.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) and in partial modification of the Notification No. 2(8)/Spl. Cell/69-SS.IV dated 30th August, 1974 of the Government of India in the late Ministry of Supply and Rehabilitation (Department of Rehabilitation), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under section 33 of the said Act shall exercisable also by the Officer-on-Special Duty (Appeal & Revisions), Government of Maharashtra, Revenue and Forests Department, in addiiton to his own duties in respect of the lands and properties within that State and forming part of the 'Compensation Pool'.

[No. 1(5)||Spl. Cell|86-SS II]

G. P. S. SAHI, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(प्रधान कार्यालय संस्थापन)

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1988

का. आ. 395 :—केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड नियम, 1964 (कारबार का संव्यवहार विनियमन) के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा के अधिकारी और आजकल राजस्व विभाग में विशेषकार्य अधिकारी (भारत सरकार के सचिव के समकक्ष) पद पर तैनात श्री एम. वी. एन. राव को दिनाक 21 दिसम्बर, 1987 के अपराह्न से सदस्य, के. उ. शु. और सी. शु. बोर्ड और अध्यक्ष, के. उ. शु. और सी. शु. बोर्ड के पद पर नियुक्त करती है। श्री राव अगला आदेश होने तक सदस्य और अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड के कार्यालय का अतिरिक्त कार्य भी देखेंगे।

[फा. स. ए.-19011/18/77-प्रशा. I]

शैलेन्द्र कुमार, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

New Delhi, the 1st January, 1988

S.O. 395.—Is exercise of the powers conferred by Rule 3 of the Central Board of Excise & Customs (Regulation of Transaction of Business) Rules, 1964, the Central Government hereby appoints Shri M. V. N. Rao, an officer of the Indian Customs & Central Excise Service and presently posted as O.S.D. (equivalent to the Secretary to the Government of India) in the Department of Revenue as Member, Central Board of Excise & Customs and also as Chairman, Central Board of Excise & Customs with effect from the afternoon of the 21st December, 1987. Shri Rao will hold the office of the Member and Chairman, Central Board of Excise & Customs as additional charge until further orders.

[F. No. 19011|18|77-Ad I]

S KUMAR, Dy. Secy

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1988

का. आ. 396 :—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है, कि उक्त अधिनियम की धारा 10-ख की उपधारा (1) और (2) के उपबंध यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता पर 24 दिसम्बर, 1987 से 23 मार्च, 1988 तक तीन महीने की अवधि के वास्ते बैंक के नियमित पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, लागू नही होंगे।

[सं. 15/21/87-बी. ओ. —III (1)]

New Delhi, the 19th January, 1988

S.O. 396.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Bankikng Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) and (2) of section 10-B of the said Act, shall not apply to the United Industrial Bank Ltd., Calcutta for a period of three months from 24th December, 1987 to 23rd March, 1988 or till the appointment of a regular whole time Chairman for that Bank, whichever is earlier.

[No. 15/21/87-B.O.III(1)]

का. आ. 397 :—बैककारी विनिययम अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10-ख की उपधारा (9) के उपबंध यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड कलकत्ता पर 24 दिसम्बर, 1987 से 23 मार्च, 1988 तक अथवा बैंक के नियमित पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक इनमे से जो भी पहले हो, उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक बैंक की चार महीने से अधिक की अवधि के वास्ते अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने की छूट प्राप्त है।

[स. 15/21/87—बी. ओ.-III(2)]

प्राण नाथ, अवर सचिव

S.O. 397.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (9) of section 10-B of the said Act shall not, to the extent they preclude the bank from appointing a person to carry out the duties of the Chairman and Chief Executive Officer beyond a period exceeding four months, apply to the United Industrial Bank Ltd., Calcutta, from 24th December, 1987 to 23rd March, 1988 or till the appointment of a regular Chairman for that bank, whichever is earlier.

[No. 15/21/87-B.O.III(2)]

PRAN NATH, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1988

का. आ. 398 :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम हिन्डन ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, :—

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) "बैंक" से हिन्डन ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नही है किन्तु अधिनियम मे परिभाषित हैं वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम में है।

3. बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही मे कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजन :—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

5. अधिवेशनों का स्थान :—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय में अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूची:—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे मे अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन :—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो होगी।

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबंध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग लेने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन.—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश-दिन न हो, उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वतः स्थगित हो जायेगा।

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष, जिस तारीख तक के लिये अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार.—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार को कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकार होगा मानो ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा।

11 कारबार के अभिलेख.—(1)(क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त कहा गया है) में रखा जायेगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसमें अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, द्वारा आद्यक्षारित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेगी।

(3) जब कोई कारबार या कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख की अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तकों में उसकी प्रविष्टि की जायेगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार रखे जायेंगे उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होगे।

[सं. एफ. 12-3/86-आर आर बी (1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 25th January, 1988

S.O. 398.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Punjab National Bank hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Hindow Grameena Bank (Meetings of Board) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Hindow Gramin Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at leas one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shal be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The meetings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified areas as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business.—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated alongwith the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting of the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) Th meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher.

Provided that where by reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of, or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place :

Provided that where a director is not present at a meeting adjourned for want of quorum the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned, send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs, be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constitute quorum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) f a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meeting of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialled or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F. 12(3)/86/RRB(1)]

का.आ. 399.— प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और आध्रा बैंक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः—(1) इन नियमों का नाम गोदावरी ग्रामीण बैंक (बोर्ड के अधिवेशन) नियम 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाः—इन नियमों में, जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से प्रादेशकि ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है।

(ख) "बैंक" से गोदावरी ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नही है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ है, जो उनके अधिनियम मे है।

3. बोर्ड के अधिवेशनो की न्यूनतम संख्याः—एक वर्ष में बोर्ड के कम से कम छह अधिवेशन होंगे और हर तिमाही में कम से कम एक अधिवेशन होगा।

4. अधिवेशनों का संयोजनः—अधिवेशनों का संयोजन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

5. अधिवेशनों का स्थान'—बोर्ड के अधिवेशन बैंक के मुख्य कार्यालय अथवा अधिसूचित क्षेत्र में किसी ऐसे अन्य स्थान पर होंगे, जिसे बोर्ड विनिश्चित करे।

6. अधिवेशन की सूचना तथा कारबार की सूचीः—(1) (क) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन का समय एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन के लिए प्रत्येक निदेशक को अधिवेशन की तारीख से साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और प्रत्येक निदेशक को यह सूचना उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जायेगी।

(ग) अधिवेशन में किये जाने के लिए प्रस्तावित कारबार की सूची उक्त सूचना के साथ ही परिचालित की जायेगी।

(घ) उस कारबार के सिवाय जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है, कोई अन्य कारबार अधिवेशन के अध्यक्ष तथा उपस्थित निदेशकों की बहुसंख्या की सहमति के बिना तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस कारबार के बारे में अध्यक्ष को एक सप्ताह की लिखित सूचना नहीं दे दी गयी है।

(2) यदि बोर्ड का आपात अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक निदेशक को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जायेगी।

7. बोर्ड का विशेष अधिवेशन.—(1) अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए कम से कम चार निदेशकों से मांग प्राप्त होने पर, बोर्ड का अधिवेशन बुलायेगा।

(2) इस मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा, जिसके लिए अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा की गयी है।

(3) अधिवेशन मांग प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर ही बुलाया जायेगा।

8. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई या चार की, इनमें से जो अधिक हो, होंगी।

परन्तु जहां इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबन्ध के कारण कोई निदेशक बोर्ड के अधिवेशन में विचार-विमर्श में भाग होने के अथवा मत देने में असमर्थ हो, तो वहां गणपूर्ति तीन की होगी।

गणपूर्ति न होने के कारण अधिवेशन का स्थगन.—यदि बोर्ड का अधिवेशन, गणपूर्ति न होने के कारण नहीं हो सका हो तो, अधिवेशन अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी स्थान एवं समय के लिए, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश-दिन हो, तो उससे अगले दिन, जो सार्वजनिक अवकाश दिन न हो उसी समय और उसी स्थान के लिये स्वतः स्थगित हो जायेगा।

परन्तु जहां गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कोई निदेशक अनुपस्थित रहा हो, वहां अध्यक्ष जिस तारीख तक के लिए अधिवेशन स्थगित हो, उससे पूर्व उस निदेशक को यह सूचना भेजेगा कि गणपूर्ति न होने के कारण उस तारीख को अधिवेशन नहीं हुआ।

10. परिचालन द्वारा कारबार.—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कारबार का कागजों के परिचालन द्वारा निदेशकों (भारत से बाहर गये निदेशकों से भिन्न) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) कोई भी कारबार जिसे उपनियम (1) के अन्तर्गत परिचालित किया गया हो और उन निदेशकों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हो, जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किये हों, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकार होगा मानो ऐसा कारबार अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया गया हो।

(3) परिचालन द्वारा पारित कोई मामला बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित किया गया माना जायेगा जिस तारीख को उस मामले पर अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किये हों।

(4) यदि कोई मामला परिचालित किया जाता है तो उस परिचालन परिणाम से सभी निदेशकों को संसूचित किया जायेगा।

(5) कागजों के परिचालन द्वारा किसी प्रश्न पर किये गये सभी निर्णयों को अभिलेख के लिये अगले अधिवेशन में रखा जायेगा।

11. कारबार के अभिलेख.—(1)(क) बोर्ड के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों को पुस्तकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यवृत्त पुस्तक कहा गया हो) में रखा जायेगा।

(ख) कार्यवृत्त पुस्तक का हर पृष्ठ यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा निदेशक, जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की हो द्वारा आद्यक्षरित या हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ऐसी पुस्तक में प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख के अन्तिम पृष्ठ पर तारीख डाली जायेगी।

(2) प्रत्येक अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इन कार्यवृत्तों की प्रतियां प्रत्येक निदेशक को भेजी जायेंगी।

(3) जब कोई कारबार का कागजों के परिचालन द्वारा किया जाये तो इस प्रकार किये गये कारबार के अभिलेख को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और कार्यवृत्त पुस्तक में उसकी प्रविष्टि की जायेगी।

(4) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त पुष्टि के लिये अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे।

(5) अधिवेशनों के वे कार्यवृत्त, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार रखे जायेंगे उनमें अभिलिखित कार्यवाहियों का साक्ष्य होंगे।

[सं. एफ. 12-3/86-आर आर बी (2)]

टी. वी. मीरचन्दानी, निदेशक

S.O. 399.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Andhra Bank hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Godavari Grameena Bank (Meetings of Board) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

(b) "bank" means the Godavari Grameena Bank.

(c) words and expressions used herein and not defined buf defined in the Act have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

2. Minimum number of meetings of the Board.—The Board shall hold at least six meetings in a year and at least one meeting in every quarter.

4. Convening of meetings.—Meetings of the Board shall be convened by the Chairman.

5. Venue of the meetings.—The metings of the Board shall be held at the head office of the bank or at such other place in the notified areas as the Board may decide.

6. Notice of meeting and list of business—(1) (a) The Chairman shall decide the time and place of every meeting of the Board.

(b) A notice of not less than fifteen days shall ordinarily be given to every director for a meeting of the Board and the notice shall be sent to every director at the address specified by him in this behalf.

(c) A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be circulated alongwith the notice.

(d) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(2) Where, it is necessary to call an urgent meeting of the Board, a notice of not less than seven days shall be given to each director.

7. Special meeting of the Board.—(1) The Chairman shall call a meeting or the Board after a requisition for that purpose has been received by him from not less than four directors.

(2) The requisition shall state the purpose for which the meeting is required to be called.

(3) The meeting shall be called not later than twenty-one days from the date of receipt of the requisition.

8. Quorum for a meeting.—A quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total number of directors or four whichever is higher.

Provided that whereby reason of the provision of sub-section (4) of section 14 of the Act any director is unable to take part in the discussion of or vote at, a meeting of the Board, the quorum shall be three.

9. Adjournment of meeting for want of quorum.—If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place.

Provided that where a director is no present at a meeting adjourned for want of quorum the Chairman shall, before the date to which the meeting stands adjourned send notice to the director that the meeting was not held on the date for want of quorum.

10. Business by circulation.—(1) A business which is to be transacted by the Board may, if the Chairman so directs be referred to directors (other than directors who are absent from India) by circulation of papers.

(2) Any business circulated under sub-rule (1) and approved by such number of directors as are necessary to constittue quotum for a meeting of the Board who have recorded their views in writing shall be as effectual and binding as if such business were decided by the majority of the directors present at a meeting.

(3) A business passed by circulation shall be deemed to be a business passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the business.

(4) If a business is circulated the result of the circulation shall be communicated to all the directors.

(5) All decisions on a question arrived at by circulation of papers shall be placed at the next meeting for record.

11. Records of business.—(1) (a) The minutes of the meetings of the Board shall be kept in book (hereinafter referred to as the Minutes Book).

(b) Every page of the Minutes Book shall be initialled or signed by the Chairman or the director, as the case may be, who presided at the meeting and last page of the record of proceedings of each meeting of such book shall be dated.

(2) Copies of such minutes shall be forwarded to each director as soon as possible after every meeting.

(3) When a business is transacted by circulation of papers, a record of business so transacted shall be signed by the Chairman and shall be entered in the Minutes Book.

(4) The minutes of each meeting shall be placed before the next meeting for confirmation.

(5) The minutes of meetings kept in accordance with the provisions of these rules shall be evidence of proceedings recorded therein.

[No. F.12(3)/86-RRB(2)]

C. W. MIRCHANDANI, Director

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1988

का. आ. 400 :—भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 (1984 का 62) की धारा 10 की उपधारा (iii) के खण्ड (घ) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री के. मनमोहन शेनोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यूको बैंक, कलकता को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के निदेशक के रूप में नामित करती है।

[संख्या एफ-7/2/87-बी ओ I]

एस. एस. हसूरकर, निदेशक

New Delhi, the 25th January, 1988

S.O. 400.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Reconstruction Bank of India Act, 1984 (62 of 1984), the Central Government hereby nominates Shri K. Manmohan Shenoi, Chairman and Managing Director, UCD Bank, Calcutta, as a Director of the Industrial Reconstruction Bank of India.

[No. F. 7/2/87-BO. I]

S. S. HASURKAR, Director.

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1988

का.आ. 401 :—केन्द्रीय सरकार औद्योगिक, वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसरण में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर उक्त निगम द्वारा 17 फरवरी, 1988 को जारी किए जाने वाले और 17 फरवरी 2003 को परिपक्व होने वाले बांडों पर देय ब्याज की दर एतद्द्वारा 11% (ग्यारह प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित करती है।

[फा. सं. 6(5)87-आई. एफ. I]

पी. के. मल्होत्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd February, 1988

S.O. 401.—In pursuance of sub-section 2 of Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government, on the recommendation of the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India hereby fixed 11 per cent (eleven percent) per annum as the rate of interest payable on the bonds to be issued by the said Corporation on 17th February, 1978 and maturing on 17th February, 2003.

[F. No. 6(5)/87-IF I]

P. K. MALHOTRA, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नयी दिल्ली, 2 फरवरी, 1988

का. आ. 402 केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स फैराडो लैबोरेट्रीज, गंजम स्ट्रीट, काकीनाडा (आ.प्र.) की यहां इससे उपाबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अकार्बनिक रसायनों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है कि संगठन अकार्बनिक रसायनों के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 के नियम 4 के उप नियम 4 के अन्तर्गत, निर्यात निरीक्षण परिषद् के किसी भी अधिकारी को निरीक्षण का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए संगठन द्वारा अपनाई गई निरीक्षण प्रणाली जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगा।

अनुसूची

1. सोडियम कार्बोनेट (1)
2. एल्युमीनियम सल्फेट (फैरिक नहीं) (1)
3. अमोनियम क्लोराईड (1)
4. मैगनीज सल्फेट (1)
5. सोडियम बाईकार्बोनेट (1)
6. कैल्शियम कार्बोनेट (1)

[फाइल सं. 5(8)/87-ई.आई.एंड ई.पी.]

एन. एस. हरिहरन, निदेशक,

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 2nd February, 1988

S.O. 402.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a period of one year from the date of publication of this notification M/s. Ferrado Laboratories, Ganjam Street, Kakinada (A.P.) as an agency for inspection of the inorganic Chemicals specified in schedule annexed hereto prior to export subject to the condition that the organisation shall give adequate facilties to any officer of the Export Inspection Council to examine the method of inspection followed by the organisation in granting the certificate of inspection under sub rule 4 of rule 4 of the Export of Inorganic Chemicals (Inspection) Rules, 1966.

SCHEDULE

1. Sodium Carbonate.
2. Aluminium Sulphate (Non-ferric).
3. Ammonium Chloride.
4. Maganese Sulphate.
5. Sodium Bicarbonate.
6. Calcium Carbonate.

[F. No. 5(8)/87-EI&EP]

N. S. HARIHARAN, Director

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1988

का.आ. 403 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य गोभा से सरसवणी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतपाबद्ध अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल, तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

अनुसूची

मोभा से सरस्वणी तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य गुजरात जिला- बडोदारा तालुका पादरा

गांव	सर्वे न.	हेक्टर	आर	सेण्टीयर
1	2	3	3	5
मोभा	कार्ट ट्रेक	0	00	90
	699	0	08	90
	700	0	07	50
	701	0	08	60
	702/2	0	03	60
	702/1	0	03	00
	703	0	00	50
	706	0	13	00
	688	0	09	00
	707	0	02	70
	कार्ट ट्रेक	0	01	70
	791/1	0	07	60
	795	0	07	20
	796	0	04	20
	1504	0	02	00
	797	0	04	00
	780/1	0	40	30
	806	0	08	00
	807	0	06	00
	775	0	05	00

[सं. ओ. 11027/52/87-ओएनजी डी.-3]

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 7th January, 1988

S.O. 403.—Whereas it appear to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from MOBHA to SARSWANI in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Maka pura Road, Baroda-390009.

And every person making such an objection shall also state specifiacally whether he wished to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM MOBHA TO SARSWANI

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padara

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Mobha	Cart track	0	00	90
	699	0	08	90
	700	0	07	50
	701	0	08	60
	702/2	0	03	60
	702/1	0	03	00
	703	0	00	50
	706	0	13	00
	688	0	09	00
	707	0	02	70
	Cart track	0	01	70
	791/1	0	07	60
	795	0	07	20
	796	0	04	20
	1504	0	02	00
	797	0	04	00
	780/1	0	40	30
	806	0	08	00
	807	0	06	00
	775	0	05	00

[No. O—11027/52/87-O.N.G.D-III]

का. आ. 404:—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2126 तारीख 30-7-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न

अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एम. एन. डी. जे. से एस. एम. सी. टी. एम. तकनीकी पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य गुजरात जिला और तालुक मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर.	सेन्टीयर
सन्थाल	612/2	0	01	80
	607/2	0	12	72
	648	0	12	84
	651	0	04	56

[सं. ओ.-11027/21/87/ओ.एन.जी./डी.-III]

S.O. 404.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2126 dated 30-7-87 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM SNDJ TO SS CTF

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Santhal	612/2	0	01	80
	607/2	0	12	72
	648	0	12	84
	651	0	04	56

[No. O-11027/21/87/O N G -D-III]

का.आ. 405.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कलोल नवागाम से कोयली फेस-II तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और, यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

अनुसूची

के. एन. के. फेस II की पाइप लाइन बिछाने के लिए राज्य गुजरात जिला. अहमदाबाद तालुका दसक्रोई

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
फतेहवाड़ी	188/189/190/9	0	09	10
	188/189/190/6	0	15	00
	188/189/190/3	0	08	50
	105/107/108/109/9	0	25	00
	105/107/108/109/12	0	02	20

1	2	3	4	5
	110टू 115	0	01	95
	6			
	232/198/199/ 200/233	0	14	70
	1			
	236, 237, 238, 240,241,242	0	16	00
	1			
	236,237,238, 240,241,242	0	11	00
	2			
	228,225,227, 230,231,239	0	03	00
	261			
	260	0	07	60
	309	0	05	10
	310+313	0	08	00
	311	0	09	00
	317,318,312, 325,314,315, 316,326,531 338,342,319 से 323	0	08	80
		0	18	50
	568	0	03	70
	339	0	11	14
	336	0	10	29
	400	0	04	13
	401	0	08	50
	402	0	00	16
	398	0	07	70
	397	0	09	10
	406	0	02	90
	410/2	0	11	26
	413/2	0	00	70
	413/1	0	01	44
	412	0	09	00

[सं. ओ.-11027/37/87/ओ.एन.जी.-डी.-III]

S.O. 405.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Kalol-Nawagan to Koyali-Phase II in Gujatay State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, objections to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wished to be here in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FOR KNK PHASE II.

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dascroi

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Fatehwadi	188/189/190	0	09	10
	9			
	188/189/190	0	15	00
	6			
	188/189/190	0	08	50
	3			
	105/107/108/ 109	0	25	
	9			
	105/107/108 109	0	02	20
	12			
	110 to 115	0	01	95
	6			
	232/198/199/ 200/233	0	14	70
	1			
	236,237,238 240,241,242	0	16	00
	1			
	236, 237,238 240, 241,242	0	11	00
	2			
	228, 225, 227 230, 231, 239	0	03	00
	261			
	260	0	07	60
	309	0	05	10
	310+313	0	08	00
	311	0	09	00

1	2	3	4	5
	317 318, 312			
	325,314, 315,	0	08	80
	316, 326, 531			
	338, 342, 319			
	to 323	0	18	50
	568	0	03	70
	339	0	11	14
	336	0	10	29
	400	0	04	13
	401	0	08	50
	402	0	00	16
	398	0	07	70
	397	0	09	10
	406	0	02	90
	410/2	0	11	26
	413/2	0	00	70
	413/1	0	01	44
	412	0	09	00

[No. O-11027/37/87/O.N.G. D.-III]

का.आ. 406 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कलोल नवागाम से कोथली-फेस-II तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडौदा 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत्।

अनुसूची

के. एन. के. फेस II की पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य गुजरात जिला : खेड़ा तालुका नड़ी याद

गांव	ब्लोकन	हेक्टर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
पलासा	1425	0	03	70
	1426	0	02	90
	1424	0	04	60
	1423	0	05	10
	1422	0	04	50
	1429	0	07	30
	1430	0	17	70
	1431	0	05	80
	1391	0	04	80
	1390	0	05	10
	1389	0	07	00
	1388	0	05	70
	1387	0	05	20
	कार्ट ट्रेक	0	00	60
	1361	0	00	40
	1365	0	03	70
	1386	0	05	90
	1372	0	06	30
	1373	0	12	90
	1371	0	04	20
	1223	0	04	08
	1219	0	07	60
	1174	0	05	50
	1206	0	01	70
	1173	0	01	20
	1172	0	06	50
	1171	0	01	00
	कार्ट ट्रेक	0	00	50
	1175	0	05	50
	1165	0	10	20
	1166	0	05	30
	1167	0	02	00
	कार्ट ट्रेक	0	00	50
	1164	0	05	40
	1123	0	06	80
	1124	0	07	50
	1130	0	07	20

1	2	3	4	5
	1100	0	09	00
	1101	0	02	00
	1090	0	11	50
	कार्ट ट्रैक	0	00	50
	996	0	02	70
	997	0	04	80
	998	0	00	45
	994	0	01	50
	1000	0	05	10
	981	0	15	90
	977	0	07	50
	980	0	03	50
	979	0	02	10
	864	0	10	50
	871	0	02	60
	872	0	03	80
	874	0	16	70
	689	0	03	70
	683	0	02	00
	685	0	04	50
	686	0	05	00
	679	0	14	00
	1131	0	04	00
	684	0	00	20

[सं. ओ. 11027/36/87/ओ.एन. जी.-डी.-III]

S.O. 406.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Kalol-Nawagoan to Koyali Phase-II in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, objections to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wished to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FOR KNK PHASE II.

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Nadiad

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Palana	1425	0	03	70
	1426	0	02	90
	1424	0	04	60
	1423	0	05	10
	1422	0	04	50
	1429	0	07	30
	1430	0	17	70
	1431	0	05	80
	1391	0	04	80
	1390	0	05	10
	1389	0	07	00
	1388	0	05	70
	1387	0	05	20
	Cart track	0	00	60
	1361	0	00	40
	1365	0	03	70
	1366	0	05	90
	1372	0	06	30
	1373	0	12	90
	1371	0	04	20
	1223	0	04	80
	1219	0	07	60
	1174	0	05	50
	1206	0	01	70
	1173	0	01	20
	1172	0	06	50
	1171	0	01	00
	Cart track	0	00	50
	1175	6	05	50
	1165	0	10	20
	1166	0	05	30
	1167	0	02	00
	Cart track	0	00	50
	1164	0	05	40
	1123	0	06	80
	1124	0	07	50
	1130	0	07	20
	1100	0	09	00
	1101	0	02	00
	1090	0	11	50
	Cart track	0	00	50
	996	0	02	70
	997	0	04	80
	998	0	00	45
	994	0	01	50
	1000	0	05	10
	981	0	15	90

1	2	3	4	5
	977	0	07	50
	980	0	03	50
	979	0	02	10
	864	0	10	50
	871	0	02	60
	872	0	03	80
	874	0	16	70
	689	0	03	70
	683	0	02	00
	685	0	04	50
	686	0	05	00
	679	0	14	00
	1131	0	04	00
	684	0	00	20

[No. O.-11027/36/87 O.N.G./D. III]

का. आ. 407:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कलोल नवागाम से कोयली-फेस-II तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बडौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

के. एन. के. फेस II की पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : आनंद

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
वलासण	539/4	0	14	00
	539/3	0	06	96
	543	0	53	70
	546/1	0	08	00
	546/2	0	08	10
	560/2	0	19	80
	561/4	0	20	20
	561/1	0	16	10
	562	0	16	90
	522	0	13	00
	518/1	0	26	40
	505/1	0	01	23
	505/2	0	10	15
	507	0	12	70
	489/2	0	27	70
	488	0	55	70
	487	0	27	60
	486	0	22	40
	474	0	06	29
	398/1+3	0	04	76
	427	0	04	15
	428	0	00	13
	426/2	0	03	36
	425/1	0	00	03
	425/2	0	08	25
	425/3	0	08	46
	425/4	0	01	22
	437	0	15	10
	435	0	00	14
	436	0	21	46
	458	0	29	60
	459/2	0	07	62

[सं. ओ.-11027/38/87/ओ.एन.जी.-डी.-III]

S.O. 407.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Kalol-Nawagaon to Koyali Phase-II in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, objections to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wished to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FOR KNK PHASE II.

State : Gujarat District : Kheda Ttaluka : Anand

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Valasan	539/4	0	14	00
	539/3	0	06	96
	543	0	53	70
	546/1	0	08	00
	546/2	0	08	10
	560/2	0	19	80
	561/4	0	20	20
	561/1	0	16	10
	562	0	16	20
	522	0	13	00
	518/1	0	26	40
	505/1	0	01	23
	505/2	0	10	15
	507	0	12	70
	489/2	0	27	70
	488	0	55	70
	487	0	27	60
	486	0	22	40
	474	0	06	29
	398/1+3	0	04	76
	427	0	04	15
	428	0	00	13
	426/2	0	03	36
	425/1	0	00	03
	425/2	0	08	25
	425/3	0	08	46
	425/4	0	01	22
	437	0	15	10
	435	0	00	14
	436	0	21	46
	458	0	29	60
	459/2	0	07	62

[No. O-11027/378/8/O.N G.-D. III]

का. आ. 408.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कलोल-नवागाम से कोयली-फैस II तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी अवधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

के. ऐन. के. फेस II की पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य . गुजरात जिला : खेडा तालुका . नडीयाद

गांव	सर्वे न.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
वडताल	77	0	10	80
	78	0	19	80
	75/10	0	05	85
	75/14	0	05	95
	75/5/ए	0	10	40
	74	0	11	56
	81	0	01	41
	33/3	0	08	20
	33/2/2	0	13	80
	33/2/1	0	13	80
	34/3	0	18	80
	34/2	0	13	40
	34/1	0	16	80
	38/2	0	16	00
	38/1	0	20	20
	43/3	0	13	80
	43/1	0	06	60
	56	0	48	60
	57/2	0	04	70
	410/3	0	10	50
	410/1	0	10	50
	409	0	11	20
	408/2	0	05	20

[सं. ओ-11027/39/87/ओ एन जी-डी.-III]

S.O. 408.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Kalol-Nawagam to Koyali Phase-II in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wished to be here in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FOR KNK PHASE II.

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Nadiad

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Vadtal	77	0	10	80
	78	0	19	80
	75/10	0	05	85
	75/14	0	05	95
	75/5/A	0	10	40
	74	0	11	56
	81	0	01	41
	33/3	0	08	20
	33/2/2 33/2/1	0	13	80
	34/3	0	18	80
	34/2	0	13	40
	34/1	0	16	80
	38/2	0	16	00
	38/1	0	20	20
	43/3	0	13	80
	43/1	0	06	60
	56	0	48	60
	57/2	0	04	70
	410/3	0	10	50
	410/1	0	10	50
	409	0	11	20
	408/2	0	05	20

[No. O-11027/39/87/O.N G.-D.III]

का. आ. 409—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कलोल-नवागम से कोयली-फेस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

अनुसूची

के. ऐन. के. फेस II की पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : आनंद

गांव	सर्वे न.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
नावली	899/2	0	01	54
	901/8	0	05	00
	901/7	0	06	60
	901/6	0	13	40
	903/5	0	04	05
	903/3	0	00	20
	903/4	0	07	50
	930/3/2	0	03	00
	930/3/1	0	03	40
	930/1/2	0	03	20
	930/1/1	0	09	00
	929/1	0	15	75
	910/ए+बी+सी	0	17	75
	913/2	0	12	00
	925/1	0	10	30
	924/1	0	18	00
	923/1	0	09	40
	921	0	13	20
	718/1	0	07	80
	717	0	08	00
	716/2	0	02	30
	716/1	0	15	40
	696	0	15	20

1	2	3	4	5
	689/5/2	0	16	10
	689/6	0	02	50
	कार्ट ट्रेक	0	01	00
	680/1	0	14	40
	682/3	0	10	39
	679/1+2	0	01	80
	678	0	00	45
	677/1	0	19	00
	612/1	0	02	00
	612/2	0	03	10
	612/3	0	03	10
	613/1+2	0	07	60
	608/3	0	08	40
	607/1+2	0	04	63
	605	0	07	80
	604/2	0	01	08
	604/1	0	13	26
	603/2	0	00	06
	599/1	0	03	60
	599/2	0	14	58
	597	0	15	11
	596	0	00	04
	593	0	00	85
	595	0	10	75

[सं. ओ.-11027/40/87/ओ. एन. जी. / डी.-III]

S.O 409.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Kalol-Koyali to Nawagam Phase-II in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wished to be here in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FOR KNK PHASE II.

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Anand

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Navli	899/2	0	01	54
	901/8	0	05	00
	901/7	0	06	60
	901/6	0	13	40
	903/5	0	04	05
	903/3	0	00	20
	903/4	0	07	50
	930/3/2	0	03	00
	930/3/1	0	03	40
	930/1/2	0	03	20
	930/1/1	0	09	00
	929/1	0	15	75
	910/A+B+C	0	17	75
	913/2	0	12	00
	925/1	0	10	30
	924/1	0	18	00
	923/1	0	09	40
	921	0	13	20
	718/1	0	07	80
	717	0	08	00
	716/2	0	02	30
	716/1	0	15	40
	696	0	15	20
	689/5/2	0	16	10
	689/6	0	02	50
	Cart track	0	01	00
	680/1	0	14	40
	682/3	0	10	39
	679/1+2	0	01	80
	678	0	00	45
	677/1	0	19	00
	612/1	0	02	00
	612/2	0	03	10
	612/3	0	03	10
	613/1+2	0	07	60
	608/3	0	08	40
	607/1+2	0	04	63
	605	0	07	80
	604/2	0	01	08
	604/1	0	13	26
	603/2	0	00	06
	599/1	0	03	60
	599/2	0	14	58
	597	0	15	11
	596	0	00	04
	593	0	00	85
	595	0	10	75

[No. O-11027/40/87/O.N.G.-D. III]

का. आ. 410 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कलोल-नवागाम से कोयली-फेस-II तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित

भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या विधि व्यवसायी के मार्फत।

अनुसूची

के. एन. के. फेस-II की पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : मातर

गाव	ब्लॉक न.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
हरीपाला	174	0	03	50
	175	0	05	70
	176	0	14	80
	177	0	06	40
	178	0	08	36
	184	0	13	19
	179	0	04	05
	182	0	16	00
	181	0	12	20
	196	0	11	40
	197	0	12	60
	200	0	30	60
	202	0	13	50
	355	0	16	20
	356	0	05	95
	419	0	10	90
	420	0	05	20
	421	0	20	10
	423	0	18	60
	433	0	14	19
	434	0	01	55
	435	0	06	96
	436	0	10	00
	437	0	03	21
	409	0	32	50
	490/1	0	34	40

[सं. ओ-11027/41/87-ओ एन. जी.-डी. III]

S.O. 410.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Kalol-Nawagam to Koyali Phase-II in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe Line, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wished to be here in person or by legal practitioner

SCHEDULE

Pipeline for KNK Phase II

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Matar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Harivala	174	0	03	50
	175	0	05	70
	176	0	14	80
	177	0	06	40
	178	0	08	36
	184	0	13	19
	179	0	04	05
	182	0	16	00
	181	0	12	20
	196	0	11	40
	197	0	12	60
	200	0	30	60
	202	0	13	50
	355	0	16	20
	356	0	05	95
	419	0	10	90
	420	0	05	20
	421	0	20	10
	423	0	18	60
	433	0	14	19
	434	0	01	55
	435	0	06	96
	436	0	10	00
	437	0	03	21
	409	0	32	50
	490/1	0	34	40

[No. O-11027/41/87/ONG-D II

का. आ. 411.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कलोल-नवागाम से कोयली-फेस-II तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड़, बडौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

के. एन के. फेस-II की पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : दसक्रोई

गाव	ब्लाक नं	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	3	5
कमोद	157	0	02	40
	158	0	13	10
	156	0	12	10
	164	0	11	90
	163	0	02	54
	178	0	00	60
	179	0	21	90
	183	0	14	90
	184	0	30	60
	195	0	05	00
	222	0	17	66
	223	0	14	36
	224	0	03	78
	209	0	17	00
	208	0	10	00
	227, 228, 232, 233 235	0	79	40

[सं ओ-11027/42/87/ ओ.एम.जी.डी.-III

S.O. 411.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Kalol-Nawagum to Koyali Phase-II in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 day from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wished to be here in person or by legal practitioner

SCHEDULE

Pipeline for KNK Phase II

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dascroi

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Kamod	157	0	02	40
	158	0	13	10
	156	0	12	10
	164	0	11	90
	163	0	02	54
	178	0	00	60
	179	0	21	90
	183	0	14	90
	184	0	30	60
	195	0	05	00
	222	0	17	66
	223	0	14	36
	224	0	03	78
	209	0	17	00
	208	0	10	00
	227, 228, 232, 233, 235.	0	79	40

[No. O-11027/42/87/ONG-D. III]

का. आ. 412.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कलोल-नवागाम से कोयली-फेस-II तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बडौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

अनुसूची

के. ऐन. के. फेस II की पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : मातर

गांव	ब्लांक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
राघवणज	38	0	03	50
	37	0	07	10
	31	0	19	00
	कार्टट्रेक	0	00	80
	30	0	04	80
	734	0	04	60
	733	0	04	50
	735	0	04	40
	730	0	05	50
	729	0	16	00
	720	0	03	30
	717	0	01	20
	716	0	06	00
	699	0	06	50
	698	0	03	50
	701	0	02	10
	702	0	02	50
	704	0	02	00
	कार्टट्रेक	0	00	60
	705	0	03	20
	682	0	03	70
	648	0	04	25
	649	0	03	00
	650	0	02	20
	651	0	04	30
	657	0	05	40
	656	0	14	50
	658	0	10	00
	605	0	14	50
	604	0	09	30
	684	0	00	30
	39	0	12	50
	40	0	04	00

[सं. ओ-11027/43/87/ ओ.एन.जी-डी-III

S.O. 412.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Kalol-Nawagom to Koyali Phase-II in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline for KNK Phase II

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Matar

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tare
1	2	3	4	5
Raghwana	38	0	03	50
	37	0	07	10
	31	0	19	00
	Cart track	0	00	80
	30	0	04	80
	734	0	04	60
	733	0	04	50
	735	0	04	40
	730	0	05	50
	729	0	16	00
	720	0	03	30
	717	0	01	20
	716	0	06	00
	699	0	06	50
	698	0	03	50
	701	0	02	10
	702	0	02	50
	704	0	02	00
	Cart track	0	00	60
	705	0	03	20
	682	0	03	70
	648	0	04	25
	649	0	03	00
	650	0	02	20
	651	0	04	30
	657	0	05	40
	556	0	14	50
	658	0	10	00
	605	0	14	50
	604	0	09	30
	684	0	00	30
	39	0	12	50
	40	0	04	00

[No. O-11027/43/87/ONG-D.III

का. आ. 413.—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में मजेरा—1 से डभका जी सी एस तक पेट्रोलियम के

परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बडौदा–9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

गजेरा–1 से डबका जी. सी. एस. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य :—गुजरात जिला:—बड़ोदा तालुका:—पादरा

गाँव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
गामेठा	380	0	11	10
	416	0	11	25
	395	0	18	30
	396	0	04	50
	कार्ट ट्रेक	0	00	60
	397	0	11	85
	399	0	10	65
	कार्ट ट्रेक	0	01	50
	328	0	12	00
	329	0	04	28
	322	0	10	95
	321	0	03	00
	319/बी	0	05	85
	319/ए	0	10	95
	320	0	00	90
	310	0	02	55
	309	0	00	75
	300	0	15	15
	299	0	07	50
	कार्ट ट्रेक	0	01	05
	237	0	08	55
	235	0	12	60
	236	0	03	75
	232	0	07	50
	230	0	07	05
	229	0	06	45
	301	0	12	45

[सं. ओ–11027/44/87 ओ.एन.जी.-डी.–III]

S.O. 413.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gajera-I to Dabka G.C.S. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act. 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Gajera-1 to Dabaka GCS.

State : Gujarat District : Baroda Taluka : Padara

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Gametha	380	0	11	10
	416	0	11	25
	395	0	18	30
	396	0	04	50
	Cart track	0	00	60
	397	0	11	85
	399	0	10	65
	Cart track	0	01	50
	328	0	12	00
	329	0	04	28
	322	0	10	95
	321	0	03	00
	319/B	0	05	85
	319/A	0	10	95
	320	0	00	90
	310	0	02	55
	309	0	00	75
	300	0	15	15
	299	0	07	50
	Cart track	0	01	05
	237	0	08	55
	235	0	12	60
	236	0	03	75

1	2	3	4	5
	232	0	07	50
	230	0	07	05
	229	0	06	45
	301	0	12	45

[No. O-11027/44/87/ONG-D-III]

का. आ. 414—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गांधार से धुवारण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

गांधार से धुवारण तक पाईप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य:—गुजरात जिला—भरूच तालुका—वागरा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर.	सेन्टीयर
गांधार.	322	2	39	17

[सं. ओ-11027/45/87-ओ. एन. जी./डी.-III]

S.O. 414.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Gandhar to Dhuvaran

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Gandhar	322	2	39	17

[No. O-11027/45/87/ONG-D. III]

का. आ. 415—यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गांधार से धुवारण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962) का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत. यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

गांधार से धुवारण तक पाईप लाईन बिछाने के लिए ।

राज्य:—गुजरात जिला:—भरूच तालुका:—आमोद

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
पुरसा	249	0	77	46

[सं. ओ-11027/46/87/ओ एन जी./डी.-III]

S.O. 415.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SCHEDULE

Pipeline from Gandhar to Dhuvaran

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Amod

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Pursa	249	0	77	46

[No. O-11027/46/87-ONG-D-III]

का. आ. 416.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गांधार से धुवारण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण, और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बडौदा–9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

गांधार से धुवारण तक लाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य:—गुजरात जिला :—भरूच तालुका :—वागरा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
चंचेवाल	284	2	53	87
	282	2	51	48
	288	4	72	30
	290	0	21	08
	292	0	40	72
	293	0	23	86
	294	0	04	79
	300	0	52	69
	299	0	33	53
	298	0	35	93
	315	0	66	90
	316	0	33	53
	317	0	16	77
	318	0	16	77
	319	0	35	93
	324	0	62	27
	327	0	09	58
	328	0	14	38
	330	0	43	11
	331	0	35	93

[सं. ओ–11027/47/87–ओ. एन.-डी./डी.–III]

S.O. 416.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Gandhar to Dhuvaran

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Survey No	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Chanchewal	284	2	53	87
	282	2	51	48

1	2	3	4	5
	288	4	72	30
	290	0	21	08
	292	0	40	72
	293	0	23	96
	294	0	04	79
	300	0	52	69
	299	0	33	53
	298	0	35	93
	315	0	66	90
	316	0	33	53
	317	0	16	77
	318	0	16	77
	319	0	35	93
	324	0	62	27
	327	0	09	58
	328	0	14	38
	330	0	43	11
	331	0	35	93

[No. O-11027/47/87/ONG-D-III]

का. आ. 417.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य मे गांधार से धुवारण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है .

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बडोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ,

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत ।

अनुसूची

गंधार से धुवारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला. बडोदरा तालुका: पादरा

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
अमोल	कार्ट ट्रेक	0	01	98
	286	0	18	72
	287	0	10	18
	288	0	01	35
	316	0	25	26
	319	0	01	81
	315	0	27	28
	314	0	51	54
	313	0	04	87
	कार्ट ट्रेक	0	02	54
	312	0	21	63
	335	0	44	18
	336	0	17	20
	337	0	12	68
	338	0	04	43
	340	0	08	26
	339	0	26	07
	कार्ट ट्रेक	0	04	43
	249	0	63	19
	342	0	11	52
	कार्ट ट्रेक	0	02	39
	42	0	27	57
	41	0	05	31
	43	0	13	42
	45	0	39	62
	50	0	02	22
	52	0	52	67
	54	0	07	20
	44	0	01	77
	कार्ट ट्रेक	0	03	98
	30	0	27	57
	61/ए	0	48	21
	63	0	10	37
	62	0	31	02
	कार्ट ट्रेक	0	07	08
	754	0	01	68
	102	0	00	89
	753	0	53	97
	कार्ट ट्रेक	0	04	65
	751	0	24	11
	740	0	38	47
	739	0	25	26
	727	0	33	40
	728	0	01	77
	730	0	29	87

[सं. ओ-11027/48/87-ओ. एन. जी./डी.-(III)]

S.O. 417.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gandhar to Dhuvaran in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390 009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Gandhar to Dhuvaran

State : Guiarat District : Vadodara Taluka : Padra

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Abhol	Cart track	0	01	98
	286	0	18	72
	287	0	10	18
	288	0	01	35
	316	0	25	26
	319	0	01	81
	315	0	27	28
	314	0	51	54
	313	0	04	87
	Cart track	0	02	54
	312	0	21	63
	335	0	44	18
	336	0	17	20
	337	0	12	68
	338	0	04	43
	340	0	08	26
	339	0	26	07
	Cart track	0	04	43
	249	0	63	10
	342	0	11	52
	Cart track	0	02	39
	42	0	27	57
	41	0	05	31
	43	0	13	42
	45	0	39	62
	50	0	02	22
	52	0	52	67
	54	0	07	20
	44	0	01	77
	Cart track	0	03	98
	30	0	27	57
	61/A	0	48	21
	63	0	10	37
	62	0	31	02
	Cart track	0	07	08
	754	0	01	68
	102	0	00	89
	753	0	53	97
	Cart track	0	04	65
	751	0	24	14
	740	0	38	47
	739	0	25	26
	727	0	33	40
	728	0	01	77
	630	0	29	87

[No. O—11027/48/87/ONG-D-III]

का. आ. 418:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में गजेरा–1 से डबका जी. सी. एस. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा–9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत ;

अनुसूची

गजेरा–1 से डबका जी. सी. एस. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : बड़ोदा तालुका : पादरा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
गवासद	86	0	10	50
	88	0	13	95
	92	0	10	65
	89/1	0	00	75

[सं. ओ–11027/49/87/ओ. एन. जी.-डी.-III]

S.O 418.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Gajera-I to Dabka G.C.S. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein ;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-390009;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Gajera-1 to Dabka GCS

State : Gujarat District : Baroda Taluka : Padara

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Gavasad	86	0	10	50
	88	0	13	95
	92	0	10	65
	89/1	0	00	75

[No. O—11027/49/87/ONG-D-III]

का. आ. 419:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में मोभा से सरसवणी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन (अधिनियम 1962-1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडौदा–9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

अनुसूची

मोभा से सरसवणी तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य: गुजरात जिला: बडोदरा तालुका पादरा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टयर	आर.	सेन्टीयर
राजुपुरा	156	0	04	90
	158	0	06	20
	159	0	02	90
	160	0	02	60
	161	0	03	80
	174	0	05	15
	175	0	02	40
	176	0	04	00

[सं. ओ–11027/50/87–ओ एन.जी.-डी.–III]

S.O. 419.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from MOBHA to SARSWANI in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-390009 ;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Mobha to Sarswani

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padra

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Rajupura	156	0	04	90
	158	0	06	20
	159	0	02	90
	160	0	02	60
	161	0	03	80
	174	0	05	15
	175	0	02	40
	176	0	04	00

[No. O—11027/50/87/ONG-D. III]

का. आ. 420—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में मोभा से सरसवणी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा–9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

अनुसूची

मोभा से सरसवणी तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य – गुजरात जिला – बडौदरा तालुका – पादरा

गाव	ब्लाक नं०	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
सरसवणी	969	0	02	00
	968	0	07	80
	967	0	06	70
	966	0	07	00
	1934	0	00	50
	965	0	07	00
	963	0	06	50
	962	0	04	80
	981	0	16	00

[सं. ओ – 11027/51/87 – ओ एन जी–डी III]
के. विवेकानन्द, डेस्क अधिकारी

S.O. 420.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from MOBHA to SARSWANI in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipe line, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipe line under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-390009 ;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Mobha to Sarswani

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padra

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Sarswani	969	0	02	00
	968	0	07	80
	967	0	06	70
	966	0	07	00
	1934	0	00	50
	965	0	07	00
	963	0	06	50
	962	0	04	80
	981	0	16	00

[No. O-11027/51/87-ONG-D. III]
K. VIVEKANAND, Desk Officer

उद्योग मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1988

का. आ. 421.—एकाधिकार तथा अवरोध व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मै. कैपिटल लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 19 आर. एन. मुखर्जी रोड, कलकत्ता–700001 है, के पंजीकरण का निरस्तीकरण अधिसूचित करती है, उक्त उपक्रम ऐसा उपक्रम है जिस पर उक्त अधिनियम के अध्याय III के भाग क के उपबंध अब लागू नहीं होते हैं। (पंजीकरण सं. 514/70)

[फा. 16/12/88 – एम. III]
एल. सी. गोयल, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 27th January, 1988

S.O. 421.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Capital Limited having its registered office at 19, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700001, the said undertakings being undertakings to which the provisions of part A Chapter III of the said Act no longer apply. (Registration No. 514/70)

[No. 16/12/88-M.III]
L. C. GOYAL, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1988

का. आ. 422.—केन्द्रीय सरकार, टैक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और टैक्सटाइल समिति द्वारा इस बाबत उसे की गई सिफारिशों पर, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 5588, तारीख 11 नवम्बर, 1985 का तुरन्त निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :—

(i) परन्तुक में,

(क) खंड (i) में, "(i)" कोष्ठक और अक्षर का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ii) का लोप किया जाएगा ;

(ii) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट अधिकारी किसी ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, किसी ऐसे माल को निर्यात करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा, यदि उसकी यह राय है कि टैक्सटाइल समिति, ऐसे कारणों से, जो ऐसा अधिकारी लेखाबद्ध करे, उस तारीख से जिसको सामग्री निरीक्षण के लिए प्रस्थापित की जाती है, एक सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसे निरीक्षण की व्यवस्था करने और उसे पूरा करने के लिए असमर्थ है।

[मिसिल नं. 12020/16/80" टीजे-II]
एन. सी. हेमराजानी, अवर सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 25th January, 1988

S.O. 422.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 17 of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), and on the recommendation made to it in this behalf by the Textiles Committee, the Central Government hereby makes the following amendment, with immediate effect in the notification of the Government of India in the Ministry of Textiles No. S.O. 5588 dated the 11th November, 1985, namely:—

In the said notification:—

(i) in the proviso,—

(a) in clause (i), the brackets and figure "(i)", shall be omitted;

(b) clause (ii) shall be omitted;

(ii) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the officer referred to in the preceding proviso may permit any such material to be exported without any such certificate, if he is of the opinion that the Textile Committee is unable for reasons to be recorded by such officer in writing, to arrange for and complete such inspection, within a period of one week from the date on which the material is offered for inspection.".

[File No. 12020/16/80-TJ.II]
N. C. HEMRAJANI, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1988

का.आ. 423.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में डा. के. सी. गर्ग, प्रोफेसर और अध्यक्ष, नेत्र विज्ञान विभाग, के. जी. मेडिकल कालेज, लखनऊ को लखनऊ विश्वविद्यालय की कोर्ट द्वारा इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया है।

अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की [illegible] रा (1) के [illegible] में भारत स[illegible]र के [illegible] पूर्व सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 138 (सं. 5-13/59 एम. ई.) तारीख 9 जनवरी, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्षक के अधीन क्रम सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"डा. के. सी. गर्ग,
प्रोफेसर और अध्यक्ष
नेत्र विज्ञान विभाग,
के. जी. मेडिकल कालेज,
लखनऊ।"

[संख्या वी. 11013/31/87-एम. ई. (पी.)]
सर्वेश्वर झा, उप सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 2nd February, 1988

S.O. 423.—Whereas in pursuance of the provision of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), Dr. K. C. Garg, Prof. and Head of Opthalmology, K. G. Medical College, Lucknow has been elected by the Court of Lucknow University to be a member of the Medical Council of India with effect from the date of issue of this Notification.

Now, therefore, in pursuance of Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health, No. S.O. 138 (No. 5-13/59-MI), dated the 9th January, 1960, namely:—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of Section 3" for serial number 25 and the entry relating thereto the following serial number and entry shall be substituted, namely:—

"25. Dr. K. C. Garg,
Prof. and Head, Deptt. of Opthalmology,
K.G. Medical College,
Lucknow."

[No. V. 11013/31/87-ME(P)]
SARWESHWAR JHA, Dy. Secy.

(स्वास्थ्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1988

का. आ. 424:—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या वी. 11016/1/85-एम. ई. (पी.) तारीख 7-11-1986 द्वारा निदेश दिया है कि वियना विश्वविद्यालय द्वारा दी गई एम. डी. आयुर्विज्ञान अर्हता भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी।

और डा. (श्रीमती) यार ब्रारा नाथ बाहजर, जिसके पास [illegible] है [illegible] कार्य के प्रयोजनों के लिए तत्समय

मेजर सोमनाथ मेमोरियल अस्पताल, दाढ़ (कांगड़ा), हिमाचल प्रदेश से संलग्न है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के खंड (ग) के अनुसरण में :—

(i) दो वर्ष तक की और अवधि को ; या

(ii) ऐसी अवधि को, जिसके दौरान डा. बारबारा नाथ वाइजर उक्त मेजर सोमनाथ मेमोरियल अस्पताल, दाढ़, (कांगड़ा), हिमाचल प्रदेश से संलग्न है, इनमें से जो भी कम है, ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिस तक पूर्वोक्त चिकित्सक का चिकित्सा व्यवसाय सीमित होगा।

[सख्या वी. 11016/1/85–एम. ई. (पी.)]

(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 25th January, 1988

S.O. 424.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Health No V. 11016/1/65-ME(P) dated the 7-11-1986, the Central Government is directed that the medical qualification, M.D. granted by the University of Vienna shall be recognised Medical qualification for the purpose of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. (Mds.) Barabara Nuth Wiser who possesses the said qualification is for the time being attached to the Major Som Nath Memorial Hospital, Dadh (Kangra), Himachal Pradesh for the purpose of a charitable work.

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

(i) a further period upto Two years ; or

(ii) the period during which Dr. Barbara Nuth Wiser is attached to the said Major Som Nath Memorial Hospital, Dadh (Kangra), Himachal Pradesh, which ever is shorter as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/1/65-ME(P)]

का.आ. 425.—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (i) के खंड (क) के अनुसरण में और सिक्किम सरकार के परामर्श से डा. एस. डी. शर्मा, एम० डी०, सर थूटब नामग्याल मेमोरियल अस्पताल, सिक्किम, गंगटोक को, इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (i) के उपबंधों के अनुसरण में स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 138, तारीख 9 जनवरी, 1960 का निम्नलिखित और संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में धारा 3 की उपधारा (i) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट शीर्षक के नीचे, क्रम सं. 19 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"19. डा. एस. डी. शर्मा,
एम. डी., ज्येष्ठ चिकित्सा विधिक विशेषज्ञ,
सर थूटब नामग्याल मेमोरियल अस्पताल,
गंगटोक (सिक्किम)"

[सख्या वी. 11013/18/87–एम. ई. (पी)]
आर. श्रीनिवासन, अवर सचिव

S.O. 425.—Whereas the Central Government in pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and in consultation with the Government of Sikkim have nominated Dr. S. D. Sharma, M.D., Sir Thutob Namgyal Memorial Hospital, Sikkim, Gangtok to be a member of the Medical Council of India with effect from the date of issued of this notification.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Ministry of Health No. S.O. 138, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated under clause (a) of sub-section (1) of Section 3 for serial number 19 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:—

"19 Dr. S. D. Sharma, M.D.
Medico-Legal Specialist,
Sir Thutob Namgyal Memorial Hospital,
Gangtok (Sikkim)"

[No. V. 11013/18/87-ME(P)]
R. SRINIVASAN, Under Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1988

का.आ. 426.—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग संकल्टेन्टस इंडिया लि. क बंगलौर स्थित कार्यालय।

2. मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेन्टस इंडिया का बोकारो स्थित कार्यालय।

3. क्षेत्रीय विकास आयुक्त, लोहा तथा इस्पात, हैदराबाद।

[सं. ई. – 11011(1)/87 – हिन्दी)]
चिरंजीव सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 29th January, 1988

S.O. 426.—In pursuance of sub rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for Official purpose of the the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby noti-

fies the following offices whereof the staff have acquired working knowledge of Hindi :—

1. Metallurgical and Engineering Consultants (India) Ltd., Bangalore.
2. Metallurgical and Engineering Consultanats (India) Ltd., Bokaro (Bihar).
3. Office of the Regional Development Commissioner for Iron and Steel, Hyderabad.

[No. E. 11011(1)/87-Hindi)]
CHIRANJIV SINGH, Jt. Secy.

परमाणु ऊर्जा विभाग

बम्बई, 14 दिसम्बर, 1987

का. आ. 427—केन्द्रीय सरकार परमाणु ऊर्जा (विकिरण सक्रिय अपशिष्ट पदार्थों का निपटान सुरक्षित रूप से करना) नियम, 1982 के नियम 2 की धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष को उक्त नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है।

[संख्या ए ई ए/30/3/84—ईआर]

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay, the 14th December, 1987

S.O. 427.—In exercise of the powers conferred by clause (vii) of rule 2 of the Atomic Energy (Safe Disposal of Radioactive Wastes) Rules, 1987, the Central Government hereby appoints the Chairman, Atomic Energy Regulatory Board of Department of Atomic Energy, Government of India as the competent authority to exercise the powers conferred on the competent authority under the said rules.

[No. AEA/30/3/84-ER]

का. आ. 428—केन्द्रीय सरकार विकिरण सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 2 की धारा (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की तारीख 12 जनवरी, 1979 की अधिसूचना सा. आ. 981 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

उक्त अधिसूचना में, "प्रधान, विकिरण बचाव प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार" के स्थान पर "अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड", प्रतिस्थापित किया जाए।

[संख्या ए ई ए/17/2/83—ईआर]

एम. राघवन, अवर सचिव

S.O. 428.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of rule 2 of the Radiation Protection Rules, 1971, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Atomic Energy No. S.O. 981 dated January 12, 1979, namely :—

In the said notification for the words "the Head, Division of Radiological Protection, Bhabha Atomic Research Centre, Department of Atomic Energy Government of India", the words "the Chairman, Atomic Energy Regulatory Board" shall be substituted.

[No. AEA/17/2/83-ER]
S. RAGAVAN, Under Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1988

का. आ. 429—पवन हंस लिमिटेड (जो पहले भारतीय हेलिकाप्टर निगम के रूप में प्रचलित था) के ज्ञापन और संस्था अन्तर्नियमों के नियम 38(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी, श्री पी. सी. सेन, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय के स्थान पर, जिनकी नियुक्ति इस मंत्रालय की 7 जनवरी, 1987 की अधिसूचना संख्या ए. वी-13015/10/86-ए. सी. के द्वारा अधिसूचित की गई थी, तत्काल से और 6 जनवरी, 1989 तक, श्री देव स्वरूप, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय को पवन हंस लिमिटेड के बोर्ड में पदेन निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

[संख्या ए. वी-13015/10/86-ए. सी.]

शान्तनु कंसल, उप सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 21st January, 1988

S.O. 429.—In exercise of the powers conferred by Article 38(a) of the Memorandum and Articles of Association of Pawan Hans Ltd. (formerly known as Helicopter Corporation of India), the President is pleased to appoint Shri Dev Swarup, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation as ex-officio Director on the Board of Pawan Hans Ltd. with immediate effect and until 6th January, 1989 in place of Shri P. C. Sen, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation whose appointment was notified vide this Ministry's notification No. AV-13015/10/86-AC dated the 7th January, 1987.

[No. AV-13015/10/86-AC]
S. CONSUL, Dy. Secy.

(पर्यटन विभाग)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1987

का. आ. 430 :—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में पर्यटन विभाग के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालयों को अधिसूचित करती है, जहां के 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है :—

भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों की सूची :—

1. भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, नई दिल्ली
2. भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, आगरा
3. भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, औरंगाबाद
4. भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, भुवनेश्वर
5. भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, बम्बई
6. भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, कोचीन
7. भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, गुवाहाटी
8. भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, इम्फाल
9. भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, जयपुर

10. भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, खुजराहो
11. भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, पणजी
12. भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, पटना
13. भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर
14. भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, वाराणसी

[सं. ई-11016 (15)/87-हिन्दी]

आर. एल. सुधीर, अपर महानिदेशक (पर्यटन)

DEPARTMENT OF TOURISM

New Delhi, the 22nd December, 1987

S.O. 430.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following subordinate office of Department of Tourism, the 80 per cent staff whereof have acquired working kniwledge of Hindi :

1. Government of India Tourist Office, New Delhi.
2. Government of India Tourist Office, Agra.
3. Government of India Tourist Office, Aurangabad.
4. Government of India Tourist Office, Bhubaneshwar.
5. Government of India Tourist Office, Bombay.
6. Government of India Tourist Office, Cochin.
7. Government of India Toursit Office, Guawahati.
8. Government of India Tourist Office, Imphal.
9. Govrenment of India Tourist Office, Jaipur.
10. Government of India Tourist Office, Khajuraho.
11. Government of India Tourist Office, Panaji.
12. Government of India Tourist Office, Patna
13. Government of India Tourist Office, Port Blair.
14. Government of India Tourist Office, Varanasi.

[No. E-11016/15/87-Hindi]

R. L. SUDHIR, Addl. Director General (Tourism)

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1988)

का. आ. 431.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने राजस्थान दूर संचार सर्किल के चीनावाद कोठी, मिरजावाला, दौलतपुरा, गणेश गढ़, 12 जी. छोटी और संगारिया ; हरियाणा दूरसंचार सर्किल के मैयर, सातरोड़, अग्रोहा और मंगाली ; उत्तर प्रदेश दूर संचार सर्किल के कन्नोज और किच्छा; तमिल नाडु दूर संचार सर्किल के पुथानमपट्टी और पलिवलम ; जम्मू तथा कश्मीर दूर संचार सर्किल के राजौरी ; मध्य प्रदेश दूर संचार सर्किल के मांडला तथा आन्ध्र प्रदेश दूर संचार सर्किल के जंगारैड्डीगुडम टैलीफोन केन्द्रों में दिनांक 1-3-1988 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-1/88-पी.एच. बी.]

पी. आर. कारड़ा, सहायक महानिदेशक (पी.एच.बी.)

MINISTRY OF COMMUNICATION

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 17th February, 1988

S.O. 431.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rule, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specifies 1-3-1988 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Cheenavad Kothi, Mirzawala, Daulatpura, Ganesh Garh, 12 G. Chotti and Sangaria Telephone Exchanges under Rajasthan Telecom. Circle; Mayar Satrod, Agroha and Mangali Telephone Exchanges under Haryana Telecom. Circle; Kannauj and Kichha Telephone Exchanges under U.P. Telecom. Corcle; Puthnampatti and Pulivalam Telephone Exchanges under Tamil Nadu Telecom. Circle; Rajauri Telephone Exchange under J&K Telecom. Circle; Mandla Telephone Exchange under M.P. Telecom. Circle and Jangareddygudem Telephone Exchange under Andhra Pradesh Telecom. Circle.

[No : 5-1/88-PHB]

P. R. KARRA, Asstt. Director General (PHB)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1988

का. आ. 432.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स कारबोरेन्डम यूनीवर्सल लि., ओखा (गुजरात) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, अहमदाबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-1-88 को प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 25th January, 1988

S.O. 432.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Ahmedabad, as shown in the Annexure, in the indusrtial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Corborandum Universal Ltd., Okha (Gujarat) and their workmen, which was received by the Central Government on 15-1-1988.

ANNEXURE

BEFORE SHRI N. A. CHAUHAN, PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL), AHMEDABAD

Reference (ITC) No. 9 of 1987

ADJUDICATION

BETWEEN

M/s. Carborandum Universal Ltd., Okha (Gujarat)

—First Party.

AND

The workmen employed under it.

—Second Party.

In the matter of termination of services of S/Smt. Deviben Devi, Jiviben L. and Kunwarben Pabba, female workmen.

APPEARANCES :

Shri M. I. Sheth, Advocate—for the First Party.

Nobody—for the Second Jarty.

AWARD

This industrial dispute between M/s. Carborandum Universal Ltd., Okha (Gujarat) and the workmen employed under it has been referred to me for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, by the Government of India, Ministry of Labour's Order No. L-29011/30/86 D. III(B) dated 12-1-1987.

2. The dispute relates to a single demand of the workmen which is as under :—

"Whether the action of the management of M/s. Carborandum Universal Ltd., Okha in terminating the services of S/Smt. Deviben Devsi, Jiviben L. and Kunwarben Pabba, Female workmen in contravention of Section 25 F of the Industrial Disputes Act, 1947 and not reinstating them and also not paying them maternity benefits is justified? If not, what relief are the workmen entitled to?"

3. In support of its demand statement of claim has been filed by Gujarat Rajya Khan Mazdoor Sangh vide Ex. 3, alleging that S/Smt. Deviben Devsi, Jiviben L. and Kunwarben Pabba were working as Quarry Labourers (Khan Mazdoors) for the last one or two years and their services have been terminated by Company on 26-3-85, 28-3-85 and 28-3-85 respectively without giving any notice or undergoing any legal formalities and thereby it has committed breach of Section 25F, B and R of the Industrial Disputes Act. It is prayed that the workmen concerned may be reinstated in service with full back wages.

4. The Company has filed its written statement vide Ex. 6 wherein it has denied that S/Smt. Jiviben Laxman and Kunverben Pala were ever their workmen. So far as Smt. Deviben is concerned, it has admitted that she had joined on 24-3-1984 as and was given when as and when the same was available. However, she left without giving any intimation to the Mines Manager concerned and the Company has not terminated her services as alleged by the Union. It has also denied the various contentions urged in the statement of claim.

5. After the respective statements of the parties, the matter was fixed for evidence on 15-10-1987. Shri M. J. Shetht, the learned Advocate for the Company was present on that date but nobody appeared on behalf of the Union. Thereafter the matter was again fixed on 17-11-1987 and 4-12-1987. But the Union did not appear through any person or send any intimation. Ultimately a registered notice was sent to the Secretary, Gujarat State Mines Workers Union on 11-12-1987 informing him that the matter was fixed for hearing on 16-12-1987 at 11.00 a.m. and if the Union will not appear, the case will be disposed of ex-parte. Ex. 8 acknowledgement slip shows that this notice was received by the Union. However, nobody appeared on behalf of the Union nor did they sent any intimation I, therefore, decide this matter ex-parte. Shri M. J. Sheth, the learned Advocate for the Company is present. The allegations made in the statement of claim have been denied by the Company in its written statement and the Union having failed to support its demand by any written or documentary evidence. I rejected the demnad for want of prosecution and dismiss the reference. No order as to costs.

Ahmedabad,

Date : 22nd December, 1987.

N. A. CHAUHAN, Presiding Officer

[No. L-29011/30/86-D.III(B)]

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1988

का. आ. 433.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, 15 विभिन्न आयरन और माईन्स के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, भुवनेश्वर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-1-88 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 27th January, 1988

S.O. 433.—In pursuance of section 17 of the Indsutrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of 15 different Iron Ore Mines and their workmen, which was received by the Central Government on 12th January, 1988.

ANNEXURE

INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA, BHUBANESWAR

PRESENT :

Shri S. K. Misra, LL.B, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar.

Industrial Dispute Case No. 5 of 1981 (Central)

Bhubaneswar, the 29th December, 1987

BETWEEN

1. The Superintendent,
Orissa Minerals Development Company Ltd.,
P.O. Thakurani, Via- Barbil-35,
Keonjhar.
2. The Manager,
Thakurani Iron Mine of Md. Serajuddin & Co.,
P.O. Thakurani, District Keonjhar.
3. The Sr. Regional Manager,
Orissa Mining Corporation Ltd.,
P.O. Barbil, District Keonjhar.
4. The Regional Manager,
Gandhamardan Iron Mines of Orissa Mining Corporation Ltd., P.O. Suakati,
District Keonjhar.
5. The Commercial Executive,
M/s. S. Lal & Co., P.O. Barbil,
District Keonjhar.
6. The Manager,
Roida Iron Mines of K. N. Ram, P.O. Barbil,
District Keonjhar.
7. The Administrative Officer,
Hindustan General Electrical Corporation Ltd.,
P.O. Barbil, District Keonjhar.
8. The Manager,
Guali Iron Mines of M. H. Rahman,
P.O. Guali, District Keonjhar.
9. M/s. Arjun Ladha,
P.O. Chaibasa, District Singhbhum.
10. M/s. S. C. Padhes, Mine Owner,
P.O. Joda, District Keonjhar.
11. The Manager,
Sulgumia Iron Mines of M/s. R. S. B. Deo,
P.O. Barbil, District Keonjhar.
12. The Manager,
Jalhari Iron Mines of M/s. K.M.C.
P.O. Banspani, District Keonjhar,
13. The Manager,
Janjang Iron Mines of M/s. H. G. Pandya,
P.O. Barbil/Jajang, District Keonjhar.
14. M/s. Rungta Mines Pvt. Ltd.,
P.O. Chaibasa, District Singhbhum.
15. M/s. Mangilal Rungta,
P.O. Chaibasa-833201, District Singhbhum.

.....First Party—Managements.

AND

Their workmen represented by the General Secretary, Keonjhar Mines & Forest Workers Union, P.O. Barbil, District Keonjhar.

.....Second Party—Workmen.

APPEARANCES :

Sri S. K. Jain, Vice President,
Sri K. S. Sahoo, D.G.M. Orissa Mining Corporation, ...For the First Party.
Sri D. C. Mohanty, President ...For the Second Party.

AWARD

1. The matter arises out of a reference made by the Government of India in the Labour Department in exercise of powers conferred inde sub-section (5) of section 12 read with clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide their Order No. L-26011/18/80-D.III(B) dated 4th March, 1981 for adjudication of the

dispute and answering the reference. The terms of reference may be quoted as follows :—

"Whether the demand of Keonjhar Mines & Forest Workers Union for a monthly salary of Rs. 400 for the unskilled workmen and pro-rata increase of wages for the piece-rated workers employed in the iron ore mines mentioned in the Annexure-I is justified ? If so, to what relief are the workmen entitled ?"

2. On the date of hearing, the representatives of M/s. S. Lal & Co. and the Orissa Mining Corporation and the President of the Union filed a Memorandum of settlement and submitted that they have settled the dispute out of court in the interest of industrial peace and harmony and prayed to pass an Award in terms of the settlement. Both the parties admitted the terms of the settlement before me. The settlement appears to be fair. A petition is also filed by the President of the Union, stating that similar settlements have been arrived at between the workmen and other employers who are parties to this proceeding. Hence, this Award is passed in terms of the settlement, in respect of the Orissa Mining Corporation and M/s. S. Lal & Co. The Memorandum of settlement do form part of the Award. A no dispute Award is passed in respect of the rest of the employers.
Dated : 29-12-87.

S. K. MISRA, Presiding Officer
[No. L-26011/18/86-B.IIIB]
V. K. SHARMA, Desk Officer

MEMORANDUM OF SETTLEMENT ARRIVED BETWEEN THE MANAGEMENT OF ORISSA MINING CORPORATION LTD., BHUBANESWAR AND THEIR WORKMEN REPRESENTED BY KEONJHAR MINES & FOREST WORKERS' UNION, BARBIL UNDER SECTION 12 & 15 OF I.D. ACT, 1947 ON 20-4-87

Representatives of the Management.

1. Shri N. C. Das, Managing Director.
2. Shri K. S. Sahoo, Sr. Admn. Officer.
3. Shri D. C. Mohanto, Regional Manager,
4. Shri G. C. Mishra, Mines Manager.

Representatives of Union.

1. Shri D. C. Mohanty, President,
2. Shri Dibakar Ray, General Secretary

SHORT RECITAL OF THE CASE

Consequent upon the revision of Minimum Wages of Iron Ore and Manganese Ore workers by Government of India on 29th October, 1986, the Keonjher Mines & Forest Workers' Union placed a demand for enhancement of piece rated wages of the miners. In order to settle the demand amicably and for arriving at a solution, the management invited the President of the Union for a joint discussion on 20th April, 1987. After prolonged discussion between the parties the following terms of settlement were made :

TERMS OF SETTLEMENT

1. The benefit of this agreement shall apply to all piece rated miners except over-burden and loading and un-loading workers engaged in the mining of the Iron Ore in the following mines of OMC Limited :

(a) Bansponi Iron Ore Mines.
(b) Barnada Kasia Iron Ore Mines.
(c) Gandhamardan Iron Ore Mines.

Piece rate for raising of 36 cft. Iron Ore (size lump) shall be Rs 20.25 (Rupees twenty and paise twentyfive) only. This applies to basic grade ore for export (sized-10 mm to 100 mm) and steel melting shop grade Iron Ore (sized-25 mm to 125 mm). For Steel Mill sized lump ore (size-10 mm to 50 mm) the piece rate shall Rs. 22.80 (Rupees twentytwo and paise eighty) only.

2. All piece-rated miners whose weekly earning falls short of the weekly minimum wages of Rs. 15.25 (Rupees fifteen and paise twenty five) only per day shall be paid short fall amounts.

3. Regarding piece-rated workers of Dubna, Roide and Dulki Manganese Mines, it has been agreed by the management to give 12 per cent rise over the existing rates. Regarding extention of the benefits of this settlement to the workers of Fagua-pit as pointed out by the President, it was decided by the management that the management will take a decision on this issue after getting a full-fledged report from Regional Manager, Barbil in this regard.

4. The demand of the Union for increasing the rate of production bonus in both the Iron Ore and Manganese Mines was also discussed in detail. The Union demanded that alongwith the increase in the rates of wages of the workers, the production bonus rates should also be increased simultaneously atleast by 12 per cent over the existing rates. It was also agreed by the management to increase this rates from the date of the revision of the wages.

5. The Union raised the question of delinking the wages from the Minimum Wages and fixation of a wage system based on piece-rates for a period of two years. It was decided to examine the matter and to further discuss the problem and finalise it within a period of four months.

6. The above negotiations shall be effective from 29th October, 1986 and will be valid till the next Notification of the Government of India.

Sd/-
(D. C. Mohanty)
Sd/-
(Dibakar Ray)

Sd/-
(N. C. Das)
Sd/-
(K. S. Sahoo)
Sd/-
(D. C. Mohanta)
Sd/-
(G. C. Mishra)

MEMORANDUM OF SETTLEMENT ARRIVED AT BETWEEN THE MANAGEMENT OF M/S. S. LAL & CO. LTD., BARBIL AND THEIR WORKMEN REPRESENTED BY KEONJHAR MINES AND FOREST WORKERS' UNION, BARBIL ON 27-5-1987

Name of the Parties :

(1) M/s. S. Lal & Co. Limited in respect of Jilling Langalota Iron Mines and Kasia Iron Mines, Post-Barbil, District Keonjhar (Orissa).

(2) The workmen of Jilling Langalota Iron Mines and Kasia Iron Mines, represented by Keonjhar Mines & Forest Workers Union, Barbil, District Keonjhar (Orissa).

Represented by :

(1) For M/s. S. Lal & Co. Limited :
   (i) Shri S. K. Jain, Vice-President (Mines).
   (ii) Shri N. Datta, Chief Superintendent (Mines)
   (iii) Shri B. M. Taparia, Commercial Executive.
(2) For Workmen :
   (i) Shri D. C. Mohanty, Presi-

(ii) Shri D. Satpathy, Vice-President

(iii) Shri D. Roy, General Secretary

(iv) Shri P. Beuria, Treasurer

(v) Shri B. Panda, Vice-President.

SHORT RECITAL

The Company and the workmen represented by Keonjhar Mines & Forest Workers' Union entered into a settlement dated 1st November, 1985. The Union demanded full and proper implementation of the Minimum Wages as per Notification by the Government of India, No. S-32019/1/86-W.C. (M W) dated 29th October, 1986. It was agreed by the parties that legal provisions and benefits accruing out of the aforesaid notification shall be implemented so far it is applicable to the Company and its workmen To give effect to the same, the following terms of settlement were agreed to out of the free volition of the parties.

TERMS OF SETTLEMENT

1. It is agreed that w.e.f. 29th October, 1986 the following emoluments for piece-rated and time rated workmen either under the department or under the contractor shall be introduced in respect of raising of different grades/quality of iron ore.

A. FOR JILLING LANGALOTA IRON MINES FROM 29-10-1986

(i) Export Quality High Grade Iron Ore	Rate per 36 CFT of Iron Ore Rs. 20.53 (Rupees Twenty and paise fifty three only). The rate of Rs. 20.53 will be total in cash.
(ii) Steel Melting Shop Grade (SMS Grade)	Rs. 21.43 (Rupees Twenty one and paise forty three only). The rate of Rs. 21.43 will be total in cash.
(iii) Burnpur/Bokaro/-Rourkela/Bhillai Ruri	Rs. 22.94 (Rupees Twenty two and paise twenty four only). The rate of Rs. 22.24 will be total in cash.
(iv) Kalinga Ruri	Rs. 24.45 (Rupees Twenty four and paise forty five only). The rate of Rs. 24 45 will be total in cash.

B. FOR KASIA IRON MINES FROM 29-10-1986

(i) Export quality High Grade Iron Ore and B/F Ruri	Rate per 36 CFT of Iron Ore. Rs. 20.53 (Rupees Twenty and paise fifty three only). The rate of Rs. 20 58 will be total in cash.
(ii) High Grade Sized Ruri	Rs. 22 24 (Rupees Twenty two and paise twenty four only). The rate of Rs. 22.24 will be total in cash.

The aove rates shall be paid w.e f 6-6-87 in respect of Kasia Iron Ore Mines and 8-6-87 in respect of Jilling Langalota from Mines and the arrear from 29-10-86 upto this date shall be paid in the 1st week of June, 1987.

C. DAILY RATED WORKMEN :

The wages of the daily rated workmen w.e f. 29-10-1986, falling under different categories shall be as follows :—

JILLING LANGALOTA IRON MINES

Sl. No.	Category	Revised Rate w.e.f. 29-10-86
	Unskilled	
1.	Water Carrier	13.75
2.	Store Boy	13 75
3.	Limoman	13 75
4.	Sweeper	13.75
	Semi-Skilled	
1.	Helper Blaster	15 25
2.	Helper of (Carpenter, Driller and Crusher Operator)	15 25
3.	Challan Mate (without a Competency Certificate)	15.25
4.	Creche Ayab	15 25
	Skilled	
1.	Driller-cum-operator	19.00
2.	Black-smith	19 00
3.	Carpenter	19.00
	Kasia Iron Mines	
	Unskilled	
1.	Water carrier	13 75
2.	Lime man	13.75
3.	Sweeper	13 75
	Semi Skilled	
1.	Helper (Driller, Blaster & Crusher operator)	15.25
2.	Carpenter Helper	15.25
3.	Explosive Carrier	15.25
4.	Creche Ayah	15.25
	Skilled	
1.	Driller	19.00
2.	Black Smith	19.00
3.	Carpenter	19.08

D. MONTHLY RATED WORKMEN :

It is agreed that the every monthly rated workmen shall be paid per month w.e.f. 29-10-86 as follows :—

(i) Skilled @Rs. 52 (Rupees Fifty two only) per month.

(ii) Semi-skilled @Rs 39 (Rupees Thirty nine only) per month.

(iii) Chowkidar @Rs. 32 50 (Rupees Thirty two and paise fifty only) per month.

However, the workmen's wages after giving the above benefit if fall short of the Minimum Wages, shall get the defecit to bring them at par with the minimum wages rate.

It is further agreed that they shall be paid their normal Annual increments from 1st January, 1987.

In addition to the above all workmen having a total service of more than three years shall be given one increment more. And workman having a service of more than 6 years shall be given two increments more. Fractions of year's service below 0 5 year shall be ignored and the same above 0.5 year shall be counted as one. This provision shall not be treated as a precedent. This will be applicable to workmen drawing salary upto Rs. 700 per month as on 31st December, 1986.

2. It is agreed that all the workmen, male and female, who are directly working in raising of Iron Ore either individually or jointly shall be treated as "MINERS".

3. (a) All workmen whether directly under the Management or under the contractor shall be provided with employment/attendance cards.

(b) The employment card and the attendance card for workmen under contractor/contractors shall be issued by the concerned contractor.

(c) It is agreed between the parties that when the raising contractor leaves the work of the company, the workmen

under him shall be employed by the new contractor or contractors who may be engaged by the Company for raising Iron Ore in the mines.

4. It is agreed that sufficient drilling & blasting shall be provided in all mines.

5. This settles all outstanding disputes in relation to wage/salary as demanded by the Union as on the date.

6. This settlement shall be filed before the Presiding Officer, (Central). Industrial Tribunal, Bhubaneswar, in I.D. Case No. 5/81 (Central) with a request to consider the above terms of settlement for the purpose of an Award in the aforesaid case.

Representing

M/s S. Lal & Co. Limited
Sd/-
1. S. K. Jain
Sd/-
2. N. Datta
Sd/-

3. B. M. Taparia

Representing
Keonjhar Mines & Forest Workers' Union
Sd/-
(1) D. C. Mohanty
Sd/-
(2) D. Satpathy
Sd/-
(3) D. Roy
Sd/-
(4) P. Beuria
Sd/-
(5) B. Panda

का. आ. 434.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ बड़ौदा के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. 434.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government.

ANNEXURE 'A'

BEFORE SHRI M. K. BANSAL, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I.D. 16/87

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bank of Baroda.

AND

Their workman—U. K. Chopra.

APPEARANCES :

For the workman—Workman in person.

For the management—Shri Dharam Singh.

INDUSTRY : Banking STATE : J & K.

AWARD

Dated 23-12-1987

Vide Central Government, Gazette notification No. L-12011/42/86-D.II(A) dated 13th March, 1987 issued under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, the following dispute was referred to this Tribunal for decision :

"Whether the action of the management of Bank of Baroda in not assigning duties of Special Assistant to Shri U. K. Chopra its senior most clerk at their Purani Mandi Jammu Branch in accordance with settlement dated 6th September, 1977 and 18th April, 1984 is justified ? If not to what relief is the concerned workman entitled to and from what date ?"

2. This reference came up for hearing before me on 18th December, 1987 at Jammu Camp Court. Management's plea was that there is no post which is required to be filled up as per settlement dated 22nd September, 1977. That uptill today Bank has not contemplated to fill the post. In view of the above the workman agreed that his reference is not tenable and he does not want to press the reference. In view of the above present reference is filed being not pressed and returned against the workman for the present.

Chandigarh,

M. K. BANSAL, Presiding Officer

[No. L-12011/42/86-D.II(A)(Pt.)]

M. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1988

का. आ. 435.—मैसर्स—कादिला लैब्रोटरीज प्राइवेट लि., 2941, जी. आई. डी. सी., इन्डस्ट्रियल एस्टेट, अंकलेश्वर, गुजरात (जी. जे./1357-ए) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3979 तारीख 1-10-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 22-10-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 21-10-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और

ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/173/83-पी. एफ. 2 (एस.एस.-2)]

New Delhi, the 28th January, 1988

S.O. 435.—Whereas Messrs Cadila Laboratories Private Limited, 2941 G.I.D.C. Industrial Estate, Ankleshwar-Gujarat (GJ/1357-A) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3979 dated the 1-10-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-10-1986 upto and inclusive of the 21-10-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the Rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already aodpted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/173/83-PF.II (SS.II)]

का.आ. 436.—मैसर्स फोर्ज एण्ड ब्लोअर कम्पनी, नरौदा, रोड, अहमदाबाद-380025 (जी. जे./20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3966 तारीख 1-10-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 22-10-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 21-10-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दिशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/58/83-पी. एफ. 2(एस. एस.-2)]

S.O. 436.—Whereas Messrs Forge and Blower Company, Naroda Road, Ahmedabad-380025 (GJ/20) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3966 dated the 1-10-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 2-10-1986 upto and inclusive of the 21-10-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submissin of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12 Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects

[No S-35014/58/83-PF II(SS II)]

का. आ. 437—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 5 के साथ पठित पैरा 4 के उपपरा (1) के अनुसरण मे, भारत सरकार, श्री एच बी अनन्था सुबाराव, को श्री एम. सी. नरसीमन के स्थान पर कर्नाटक के लिए कर्मचारी भविष्य निधि की प्रादेशिक समिति के सदस्य के रूप मे नियुक्त करती है और भारत सरकार के श्रम मत्रालय की अधिसूचना स का आ. 3561 तारीख 29 सितम्बर, 1986 भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3(ii) मे दिनांक 11 अक्तूबर 1986 को प्रकाशनार्थ हुई है ।

उक्त अधिसूचना क्रम स. 9 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं और प्रविष्टियां रखी जायेगी अर्थात् :—

"श्री एच. बी. अनन्था सुबा राव,
महा सचिव
आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस
कर्नाटक राज्य समिति
न. 37, 16 मन रोड
एम. सी. ले. आऊट, विजया नगर
बगलौर-560040"

[फा. स. बी-20012/2/83-एस. एस.-II]
ए०के० भट्टाराई, अवर सचिव

S O 437—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, the Central Government hereby appoints Shri H V Anantha Subba Rao as a Member of the Regional Committee for the State of Karnataka in place of Shri M C Na simhan and make the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Labour No S O 3561, dated the 29th September, 1986 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 11th October, 1986

In the said notification against Serial No 9, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely —

'Shri H V Anantha Subba Rao,
General Secretary,
All India Trade Union Congress,
Karnataka State Committee,
No 37, 16th Main Road,
MC I ay Out Vijaynagar,
Bangalore-560040"

[No V-20012/2/83-SS II]
A K BHATTARAI, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988